गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 275
दि. 06.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर आज भारत सरकार, नगालैंड सरकार और ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ENPO नगालैंड के छह पूर्वी जिलों के आठ मान्यता प्राप्त नगा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और नगालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफिउ रियो की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से नगालैंड के छह जिलों — तुएनसांग (Tuensan), मोन (Mon), किफिरे (Kiphire), लॉन्गलेंग (Longleng), नोकलाक (Noklak) और शमाटोर (Shamator) —के लिए फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा और FNTA को 46 विषयों के संबंध में शक्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन विवादमुक्त उत्तर पूर्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उग्रवादमुक्त, हिंसामुक्त, विवादमुक्त और विकसित नॉर्थ पूर्वी की जो कल्पना की है उसमें हम आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले पूर्वोत्तर में कई हथियारबंद ग्रुप्स और विवाद उत्तर पूर्व की शांति को बिखराव की दिशा में ले जाते थे। साथ ही कई अंतर राज्य विवाद राज्यों की शांति को भंग करते थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर विवाद का समाधान खोजने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें केवल समझौते करती थीं, लेकिन मोदी सरकार की परंपरा रही है कि हम जो समझौते करते हैं, उन्हें अक्षरशः और भावनात्मक रूप से पूर्णतः लागू भी करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वे ENPO के प्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारत सरकार पूर्वी नागालैंड के विकास में सहायता भी करेगी और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएगी। भारत सरकार ईस्टर्न नागालैंड के विकास में मदद भी करेगी और जिम्मेदारी भी उठाएगी। श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि निर्धारित की जाएगी तथा गृह मंत्रालय establishment के लिए प्रारंभिक व्यय भी वहन करेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2021-22 में एठढड के प्रतिनिधियों से कहा था कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर विवाद का समाधान ढूँढना चाहती है। ENPO भरोसा रखे और democratic process में हिस्सा ले उन्हे उचित न्याय और सम्मान दोनों जरूर मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि आज उन्हे बहुत हर्ष हो रहा है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा ENPO और नगालैंड सरकार बीच लंबे समय तक एक ब्रिज के रूप में काम किया जाने के बाद आज हम हम इस विवाद को हल कर सके हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि हम सब एठढड क्षेत्र और इसके कूटनीतिक महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नगालैंड की रचना के बाद ईस्टर्न नागालैंड के नागरिकों के मन में लगातार यह भाव था कि उन्हे न्याय नहीं मिल रहा है। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने नगालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफिउ रियो जी से बात की थी और रियो जी ने बड़े हर्ष के साथ कहा था कि वे एठढड की सारी मांगों को पूरे मन के साथ सुनेंगे, चर्चा करेंगे और स्वीकार भी करेंगे। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री नेफिउ रियो का धन्यवाद करते हुए कहा कि नगालैंड सरकार, श्री रियो के मंत्रिमंडल के साथियों और राज्य के दोनों सांसदों ने बहुत बड़े मन के साथ इस नेगोशिएशन को लॉजिकल अंत तक पहुंचाया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज एक बहुत लंबे समय से चल रहे विवाद का सुखद अंत हुआ है। उन्होंने ईस्टर्न नागालैंड के सभी लोगों, एठढड के सभी संघर्षरत संगठनों, नगालैंड के मुख्यमंत्री, कैबिनेट और सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि नगालैंड में सारे विवाद समाप्त होने की दिशा में हम आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि अब ईस्टर्न नगालैंड के विकास के बीच में कोई रोड़ा नहीं रहेगा। भारत सरकार और नगालैंड सरकार दोनों मिलकर ईस्टर्न नगालैंड के विकास को आगे बढ़ाएंगे।

यह समझौता, अन्य बातों के अलावा, ऋठळअ के लिए एक मिनी-सचिवालय के गठन का प्रावधान करता है, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव द्वारा किया जाएगा। साथ ही, पूर्वी नगालैंड क्षेत्र के लिए विकास व्यय का आबादी और क्षेत्रफल के अनुपात में बंटवारा भी किया जाएगा। हालांकि, यह समझौता भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(अ) के प्रावधानों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।

यह अनूठी व्यवस्था पूर्वी नगालैंड के समग्र विकास की कल्पना करती है, जिसमें वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर निर्णय-प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे का तेज विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और संसाधनों का अधिकतम उपयोग शामिल है।

यह समझौता पूर्वोत्तर के लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी विवादास्पद मुद्दों को संवाद के माध्यम से हल करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को भी सिद्ध करता है कि समाधान केवल आपसी सम्मान और संवाद पर आधारित बातचीत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, न कि हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से।

चाइनीज मांझे से मौत: सीएम योगी ने लगाई रोक, हरकत में आए प्रशासन ने शुरू की छापेमारी, कल हुई थी दर्दनाक मौत

लखनऊ , (जीएनएस)।

यूपी में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं, इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध सख्त निर्देश जारी किए हैं।

राजधानी लखनऊ के बाजारखाला में चीनी मांझे में फंसकर एक युवक की मौत के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और लखनऊ शहर में पतंग की कई दुकानों पर छापेमारी की है। शहर के हैदरगंज और मोतीझील इलाके में पुलिस ने

छापेमारी की है। मोतीझील इलाके में डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, एडीसीपी धनंजय सिंह विक्रम और बाजारखाला थाना पुलिस ने छापेमारी की।

बुधवार को बाजारखाला में पतंग की डोर ने एक युवक का गला रेत गया। इस दौरान गले की नस कट जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, कुछ दिन पहले हवा में उड़ती पतंग के तार के हाईटेंशन लाइन पर गिर जाने से मेट्रो मेट्रो ट्रेनें जहां की तहां रुक गई थीं।

बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। मांझे के इस्तेमाल पर रोक के लिए पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी जिसकी उच्चस्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

लखनऊ के बाजारखाला हैदरगंज ओवरब्रिज पर बुधवार दोपहर मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार दुबग्गा के सीते बिहार निवासी सैयद शोएब (34) की गर्दन कटने मौत हो गई।

'सत्ता बचाना ही एक मात्र लक्ष्य', मोदी का दीदी पर तीखा हमला, घुसपैठ पर घिरी टीएमसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कई मुद्दों के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 'एक क्रूर सरकार' शासन कर रही है, जो पतन के हर पैमाने पर नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन दूसरों को उपदेश दे रही है। 'राज्य के लोगों का भविष्य अंधकार में है, इन्हें कोई चिंता नहीं है। उनके मुताबिक, मौजूदा सरकार (ममता बनर्जी) का लक्ष्य सत्ता में बने रहना है, चाहे इसके लिए आम जनता को कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े।' प्रधानमंत्री ने कहा कि 'दुनिया के कई समृद्ध देश अवैध निवासियों को अपने यहां से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि भारत में कुछ लोग घुसपैठियों का बचाव कर रहे हैं।

अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ के लिए एनआईएम-जेआईएम एवं डब्ल्यूएस के संयुक्त अभियान को हरी झंडी

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 5 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6,961 मीटर की ऊंचाई वाला यह पर्वत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और एशिया के बाहर का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह संयुक्त अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस), पहलगाम द्वारा संचालित किया जा रहा है।

रक्षा मंत्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान को कर्मियों को साहस, दृढ़ता और संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने की सराहना की। टीम को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि इस दुर्गम शिखर पर चढ़ाई करना केवल शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि नेतृत्व, टीम वर्क और मानसिक दृढ़ता की सच्ची परीक्षा है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों की पहचान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सदस्य दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च शिखर और एशिया के बाहर सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे।

छह सदस्यीय दल में उच्च प्रशिक्षित प्रशिक्षक शामिल हैं - कर्नल

हेम चंद्र सिंह, कैप्टन जी संतोष कुमार, श्री दीप बहादुर साही, श्री विनोद गुसैन, नायब सिपाही भूपिंदर सिंह और हवलदार रमेश कुमार। यह यात्रा 6 फरवरी, 2026 को शुरू होगी और अभियान के महीने के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है।

एकोनकागुआ पर्वत पर प्राप्त ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास देश भर के युवाओं, सशस्त्र बलों के कर्मियों और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के सुरक्षित, सशक्त और अधिक प्रभावी प्रशिक्षण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगा।

यह अभियान वैश्विक स्तर पर साहसिक गतिविधियों और पर्वतीय अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति का प्रतीक भी है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में ग्वाटेमाला की सामाजिक विकास उप मंत्री महामहिम से भेंट की

(जीएनएस)।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग की बैठक में ग्वाटेमाला की सामाजिक विकास उप मंत्री क्लाउडिया टेरेसा वैलेंजुएला लोपेज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्वाटेमाला के साथ सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के दौरान महिला नेतृत्व और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भारत के समग्र सरकारी दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से जुड़ी प्रमुख पहलों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसके साथ ही, उन्होंने स्वयं-सहायता समूहों, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पीएम पोषण स्कूली भोजन योजना और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए भारत के अनुभव सामने रखे और सर्वोत्तम नियमों को साझा करने की भारत की तत्परता भी व्यक्त की। लड़कियों के लिए शक्तिसैट वैश्विक एसटीईएम पहल में ग्वाटेमाला का शामिल होना अत्यंत प्रेरणादायक था।

दोनों पक्षों ने लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी समुदायों के कल्याण के लिए और अधिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंखुड़ी पोर्टल के बारे में जानकारी साझा की।

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में आज भारत और खाड़ी सहयोग परिषद-जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में अपर वाणिज्य सचिव और मुख्य वार्ताकार श्री अजय भादू और खाड़ी सहयोग परिषद सचिवालय के मुख्य वार्ताकार डॉ. राजा अल मरजूकी ने इस पर हस्ताक्षर किए।

संदर्भ शर्तें जीसीसी-भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को निर्देशित करेंगे, इसके दायरे और तौर-तरीके परिभाषित करेंगे।

हस्ताक्षर समारोह में श्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वैश्विक हित में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता निश्चितता और स्थिरता लाएगा, जिससे दोनों पक्षों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुक्त व्यापार समझौते से वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह और निवेश आकर्षित होगा। साथ ही समझौते से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ने से दोनों पक्षों के बीच गहरे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव और मुख्य वार्ताकार डॉ. अल मरजूकी ने इस बात पर जोर दिया कि खाड़ी सहयोग परिषद और भारत के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की दिशा में वार्ता की शुरूआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता भारत और जीसीसी के बीच संबंधों में मजबूती लाएगा जो विशेष रूप से मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में अहम है।

डॉ. राजा अल मरजूकी ने यात्रा के दौरान वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल से मुलाकात की और भारत और जीसीसी के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी मजबूत करने और परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

भारत-खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता भारत के व्यापार और वाणिज्य में दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहे महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ व्यापार बढ़ाने और विस्तारित करने की अपार क्षमता प्रदान करता है।

नीलामी, वित्तीय सुधारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने की पहलों के माध्यम से 5जी रोलआउट में तेजी

सरकार उच्च सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए देश के सभी भागों में दूरसंचार सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध: संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी, वित्तीय सुधारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने की पहलों के माध्यम से 5जी रोलआउट में तेजी ला रही है

(जीएनएस)।

सरकार देश भर में उच्च सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए दूरसंचार सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्विस परफॉर्मेंस का आकलन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा तय क्वालिटी ऑफ सर्विस (क्यूओएस) बेंचमार्क के आधार पर किया जाता है।

हाल ही में, ट्राई ने इन क्यूओएस बेंचमार्क को संशोधित किया है, जिससे वे और सख्त हो गए हैं और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक ग्लाइड पाथ लागू किया है। इन बेंचमार्क में कॉल ड्रॉप रेट, पैकेट लॉस और सर्विस डाउनटाइम जैसे खास परफॉर्मेंस पैरामीटर शामिल हैं।

इन मेट्रिक्स के लिए आंकड़े, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स

(टीएसपी) से सुनियोजित तरीके से एकत्र किए जाते हैं, और डिटेल्ड कम्प्लायंस रिपोर्ट हर महीने सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित की जाती हैं।

दिसम्बर 2025 की ट्राई रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (एलएसए) में सभी टीएसपी ने कॉल ड्रॉप रेट सहित नेटवर्क से जुड़े पैरामीटर्स के लिए सभी क्यूओएस बेंचमार्क पूरे किए। खास तौर पर, पुणे जिले में, सभी टीएसपी ने 4जी/5जी नेटवर्क के लिए ट्राई के क्यूओएस बेंचमार्क का पालन किया।

सेवा की गुणवत्ता को और सुरक्षित रखने के लिए, जनता से प्राप्त जानकारी के लिए एक खास सिस्टम बनाया गया है। नागरिक केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के जरिए शिकायतें दर्ज करके खराब सर्विस की रिपोर्ट कर सकते हैं। विभाग इन शिकायतों का विश्लेषण करता है और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित टीएसपी के साथ सीधे कोऑर्डिनेट करता है।

खास इलाकों की बात करें तो, वर्ष 2025-26 के दौरान हिंजेवाड़ी और बारामती में कॉल ड्रॉप से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं के बारे में बहुत कम सर्विस शिकायतें दर्ज की गईं - हिंजेवाड़ी में तीन और बारामती में एक।

सितम्बर 2025 में ट्राई ने पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में एक इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट किया। इसमें देखा गया कि सभी टीएसपी ने नेटवर्क पैरामीटर और कॉल ड्रॉप रेट के लिए क्यूओएस बेंचमार्क पूरे किए।

दीदी की चुनावी रेवड़ी! बेरोजगार युवाओं को ₹1500 महीना-महिलाओं को ₹500 ज्यादा-कैसे मिलेंगे?

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया है, जिसे चुनावी साल की 'रेवड़ी' माना जा रहा है। बजट में महिलाओं, युवाओं और गिग वर्कर्स पर फोकस है, खासकर लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपये की मासिक बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसे 'जन-केंद्रित' बताया, लेकिन विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति कह रहा है। लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल की फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर फोकस करती है। यह 2021 में लॉन्च हुई, और अब राज्य की करोड़ों महिलाओं को हर महीने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से पैसे मिलते हैं। योजना का मकसद: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू खर्चों में मदद और वोट बैंक मजबूत करना। चुनावी साल में इसे 'रेवड़ी' कहा जा रहा है, क्योंकि यह महिलाओं के बीच TMC की पॉपुलैरिटी बढ़ाती है।

सम्पादकीय

सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव भी हैं

सोशल मीडियाः संवाद का माध्यम या निजता का संकट? आज संचार क्रांति का युग है। हर कोई सोशल मीडिया, एआई का प्रयोग कर रहा है। आधुनिक दौर में सोशल मीडिया ने हमारे अनेक कार्यो को आसान और सरल बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया ने संवाद को जितना सरल और व्यापक बनाया है, उतना ही जटिल निजता का प्रश्न भी खड़ा कर दिया है। आज व्यक्ति अपने जीवन के निजी क्षण–तस्वीरें, रील बनाकर अपने विचार, स्थान और दिनचर्या स्वेच्छा से सार्वजनिक मंचों पर साझा कर रहा है। यह सब आमतौर पर सोशल मीडिया मंचों पर साझा करना कभी–कभी आत्म–अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, तो कई बार अनजाने में अपनी निजता को जोखिम में डालने का कारण बन जाता है। 'लाइक' और 'व्यू' की होड़ में निजी सीमाएँ धुंधली होती जा रही हैं। यहां यदि हम सरल शब्दों में कहें तो आज के समय में तकनीक हमारी ज़िदगी की पल–पल की अहम व महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने काम आसान और तेज़ कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है–निजता का खतरा। आज के समय में अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है और वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि ऐप या प्लेटफॉर्म पर साइन–अप करते समय जो निजी जानकारी वे देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कई बार यह जानकारी हमारी अनुमति के बिना किसी और को दी जा सकती है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत ही नहीं आज संपूर्ण विश्व स्तर पर स्मार्टफोन उपयोग तेजी से सर्वव्यापी हो चुका है। 2025 के आसपास उपलब्ध ताज़ा वैश्विक अनुमानों के अनुसार दुनिया में लगभग 6.8–7.1 अरब लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि सिय स्मार्टफोन डिवाइसों की संख्या 7 अरब से अधिक मानी जाती है, क्योंकि कई उपयोगकताओं के पास एक से अधिक फोन हैं। इसका अर्थ यह है कि वैश्विक आबादी का करीब 85–90 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी रूप में स्मार्टफोन से जुड़ चुका है। यदि हम यहां पर भारत की बात करें तो देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन चुका है। साल 2024–2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्मार्टफोन उपयोगकताओं की संख्या लगभग 65–70 करोड़ (650–700 मिलियन) है, जो वुल जनसंख्या का करीब 45–50 प्रतिशत बैठती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और 4जी/5जी नेटवर्व के विस्तार के कारण यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2026 तक भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता 100 करोड़ के आसपास पहुँच सकते हैं । इस ाम में यहां यह गौरतलब है कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सऐप को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी वंपनी नागरिकों की निजी जानकारी के साथ मनमानी नहीं कर सकती और निजता के अधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का जमाना डिजिटल है और इस डिजिटल युग में आज मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार जैसी जगहों पर हमें अपनी निजी और कभी–कभी बायोमेट्रिक जानकारी भी देनी पड़ती है। अगर यह जानकारी गलत हाथों में चली जाए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। समस्या यह भी है कि यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारी जानकारी आखिर कहां–कहां पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर भी यही खतरा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नियम और शर्ते पढ़े बिना ही 'सहमति' दे देते हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारिता–आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक शुभारंभ किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली सहकारिता–आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1,200 से अधिक 'सारथियों' (ड्राइवर पार्टनर्स) ने भाग लिया, जो भारत टैक्सी के चालक सशक्तिकरण और सहकारी स्वामित्व आधारित मॉडल के प्रति व्यापक समर्थन को दशार्ता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक का एक मॉडल तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामख्या तक सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सार्थियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। श्री शाह ने कहा कि जब पहली बार उन्होंने संसद के सामने सहकार टैक्सी का विषय रखा तो बहुत सारे लोगों, खासकर टैक्सी परिचालन से जुड़ी कंपनियों, ने सवाल उठाया कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को 'सहकार' और 'सरकार' के बीच का भेद नहीं मालूम है। श्री शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं रही, बल्कि सहकार (उङ्ङ्गस्री१ ३ङ्गल्ल) टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि शायद पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी अनूठी कंपनी अस्तित्व में आ रही है, जिसका असली मालिक कोई व्यक्ति या बाहरी कंपनी नहीं, बल्कि टैक्सी चलाने वाला सारथी ही है। सहकार टैक्सी से जुड़े हर एक सारथी भाई–बहन ही इस सहकारी टैक्सी समिति के सच्चे मालिक हैं। उन्होंने कहा कि यह संकल्पना सहकार टैक्सी से जुड़ने वाले सारथियों के जीवन, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में आमूल–चूल परिवर्तन लाने वाली है। श्री शाह ने यह भी कहा कि हमारे देश में पहले ऐसे कई मॉडल सफल हो चुके हैं। सिर्फ 11 दूध उत्पादकों ने अमूल की शुरूआत की थी। आज गुजरात में 36 लाख से अधिक पशुपालक महिलाओं का विशाल वटवृक्ष खड़ा हो चुका है। यह पशुपालक महिलाएं सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं। उन्होंने कहा कि यह मॉडल दशार्ता है कि जब आम लोग स्वयं मालिक बनते हैं, तो छोटी शुरूआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है। उन्होंने कहा कि पशुपालक बहनें आज दूध बेचकर एक करोड़ रुपए तक की सालाना कमाई कर रही हैं, जो सहकारी मॉडल का कमाल है।

श्री अमित शाह ने टैक्सी सारथियों से अपील की कि वे अभी भी टैक्सी चलाते हैं, सहकार टैक्सी से जुड़ने के बाद भी टैक्सी चलाएँगे, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क होगा। उन्होंने कहा कि अभी टैक्सी का पहिया किसी और की जेब में पैसे डालता है, लेकिन अब सारथियों की टैक्सी के पहिये की कमाई सारथियों की जेब में ही जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विचार सहकारिता की भावना से ही जन्म लेता है। सहकारिता का असली अर्थ यही है कि जब ढेर सारे छोटे–छोटे पूंजी वाले लोग अपनी ताकत को

एकत्रित कर लेते हैं, तो वे मिलकर बहुत बड़े–बड़े काम कर पाते हैं। जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है, वे अकेले बड़ा काम करते हैं और मुनाफा भी कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। श्री शाह ने कहा कि आज जिस सहकारिता मॉडल की बात की जा रही है, वही आज के समय में सबसे नई और सबसे सफल शुरूआत है। उन्होंने कहा कि अब टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई के लिए नहीं, बल्कि टैक्सी सारथियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए घूमेगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत में कई विश्व–स्तरीय सहकारी मॉडल खड़े हो चुके हैं, जिनमें अमूल, इफको, कृभको जैसी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी सहकारी संस्था में शुरूआती पूंजी बहुत बड़ी नहीं थी। इसी तरह सहकार टैक्सी में सबसे बड़ी शेयर पूंजी सिर्फ 500 रुपये है और वही 500 रुपये सारथियों को असली मालिक का दर्जा दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह छोटी सी राशि टैक्सी सारथियों की मेहनत, आत्मसम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की नींव बनने जा रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हर पाँच साल पर होने वाले चुनाव के बाद टैक्सी सारथियों द्वारा चुने गए दो प्रतिनिधि बोर्ड में बैठेंगे। वे ही उनके हितों की देखभाल करेंगे और उनके लिए फैसले करेंगे। यही सहकारिता की आत्मा और सच्चे मालिकाना हक की भावना है। उन्होंने कहा कि सहकार टैक्सी कुल मुनाफे में सिर्फ 20 फीसदी पैसे ही अपने पास रखेगी, यानि 100 रुपए में से 20 रुपए ही सहकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक सारथी ही हैं। श्री शाह ने कहा कि सारा मुनाफा भारत टैक्सी से जुड़े सारथी के अकाउंट में ही जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़े 20 रुपए के मालिक भी सारथी ही होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी की कल्पना मौजूदा तीनों प्रकार के टैक्सी वाहनों को एक साथ जोड़कर की गई है जिसमें चार पहिया टैक्सी, तीन पहिया और दो पहिया वाहन शामिल हैं। उन्होंने देश की मातृ शक्ति को संदेश दिया कि भारत टैक्सी उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने सारथी दीदी की एक खास संकल्पना तैयार की है जिसके तहत आने वाले समय में ऐप में 'सारथी दीदी' के लिए एक अलग विंडो होगी, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल 'सारथी दीदी' ही पिक करने आएंगी। श्री शाह ने कहा 'सारथी दीदी' दो पहिया वाहन लेकर आएंगी और बहुत कम किराए में सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी और व्यावहारिक राहत साबित होगी। आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से देश की मातृ शक्ति को एक सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। यह सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इफको टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कुल नौ प्रमुख संस्थाओं के साथ भारत टैक्सी ने समझौता (एमओयू) किया है। इन समझौतों के जरिए भारत टैक्सी के ग्राहकों को कई अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेंगी और साथ ही इन सभी संस्थाओं को भारत टैक्सी की सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएँ अब सहकार टैक्सी की सफलता में हिस्सेदार बन चुकी हैं। यह स्वामित्व मॉडल पर आधारित नया टैक्सी कॉन्सेप्ट आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है, जो न केवल सारथियों के लिए मालिकाना हक की भावना लाता है, बल्कि यात्रियों और विभिन्न संस्थाओं के लिए भी एक भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प प्रस्तुत करता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी द्वारा तय किया गया फिक्स्ड चार्ज सारथियों के अकाउंट से अलग रहेगा। इसके अलावा, भारत टैक्सी सारथियों की पसीने की कमाई से एक प्रतिशत भी कमीशन नहीं काटेगी, जिससे उनकी समृद्धि तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य कंपनी की पूंजी को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत टैक्सी के असली मालिक, सारथी भाइयों और सारथी दीदियों, का मुनाफा और आय बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान सीधे सारथी के अकाउंट में तत्काल ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी भी सारथी का अकाउंट बिना उचित सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, सारथियों का भी दायित्व है कि वे ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी टैक्सी की गुडविल बनाए रखें और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शिकायतों की सुनवाई के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अब तक बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस और भारी कमीशन जैसी बातें कंपनी की बैलेंस शीट को मोटा करती थीं और सारथी की कमाई को घटाती थीं। भारत टैक्सी में ऐसी कोई फीस या कमीशन की व्यवस्था ही नहीं है और सारथी ही मालिक होंगे। यह विचार पश्चिमी सोच वाले लोगों को शायद समझ न आए, लेकिन यही सहकारिता की असली ताकत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की शुरूआत सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की भी शुरूआत है। पिछले 125 वर्षों से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि सहकारी मॉडल को नए–नए क्षेत्रों में ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मालिकाना हक वाला मॉडल तैयार कर रहा है। आने वाले समय में हम तीन–चार ऐसे क्षेत्रों में इस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, जहां मेहनत करने वाले व्यक्ति के पसीने और परिश्रम का फल उसी के पास रहेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी के चार मूल मंत्र हैं—स्वामित्व सुरक्षा कवच , सम्मान और सबका पहिया, सबकी प्रगति, यानी सभी के लिए लाभांश का उचित वितरण। इन्हीं चार उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरूआत हुई है और आने वाले समय में यह एक बहुत सफल प्रयोग साबित होगा। उन्होंने कहा कि 6 जून 2025 को इसकी स्थापना हुई और आज से यह कमर्शियली लॉन्च हो रही है। महज 8 महीनों के भीतर दिल्ली और गुजरात में किसी भी अन्य टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किसी अन्य कंपनी ने नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे सारथी भाइयों–बहनों को इंश्योरेंस, सरकारी रोजगार योजनाओं, लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ स्वतः मिल सकेगा। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि हर सारथी को पूरा सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2020–21 में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की थी। अब 2025–26 के बजट में भारत सरकार देश भर के सवा करोड़ के लिए ढेर सारी योजनाएं और सुविधाएं लेकर आई हैं। पहले ई–श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनकी पेंशन कटती थी या जो औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक के रूप में पंजीकृत थे। अब इस सीमा को हटाकर देश के सवा करोड़ ॠ हङ्ग१'ि१२ ई–श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी से जुड़े सभी सारथी अब आसानी से ई–श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपने और अपने परिवार के लिए स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। भारत टैक्सी से जुड़ते ही सारथियों को यह मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध अन्य कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी आपके लिए अपने आप सक्रिय हो जाएंगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी का मॉडल न केवल सारथियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने दमदार नए डियो 125 –एडिशन के साथ क्लीन और एलिगेंट शाइन 125 लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने आज दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए डियो 125 –एडिशन, जिसकी कीमत ₹87,733 है, और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन, जिसकी कीमत ₹86,211 है (दिल्ली एक्स–शोरूम)। आज के बदलते राइडर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए ये दोनों स्पेशल एडिशन एक रिफ्रेश्ड आइडेंटिटी, आकर्षक नए ग्राफिक्स और प्रीमियम डिजाइन एन्हांसमेंट्स के साथ पेश किए गए हैं, जो तेजी से बढ़ते भारतीय टू–व्हीलर मार्केट में इनकी अपील को और बढ़ाते हैं।

नए स्पेशल एडिशन पेश करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और सीईओ श्री त्सुत्सुमु ओतानी ने कहा, 'होंडा में हम लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स लाने का प्रयास करते हैं जो भारत के न्यू–एज राइडर्स की आकांक्षाओं से जुड़ें। बिल्कुल नया डियो 125 –एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन, स्टाइल की नई अभिव्यक्तियां पेश करने के साथ–साथ उस भरोसे और विश्वसनीयता को भी दशार्ते हैं, जिसकी उम्मीद ग्राहक होंडा से करते हैं। ये लिमिटेड एडिशन एक्सप्रेसिव डिजाइन को होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी के साथ जोड़ते हैं, ताकि हर राइड आत्मविश्वास भरी और सहज महसूस हो।'

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, श्री योगेश माथुर ने कहा, 'डियो 125 –एडिशन होंडा की अपनी जेन ` डिजाइन टीम द्वारा तैयार की गई बोल्ड और यूथफुल एनर्जी के साथ आता है, जो आज के युवा राइडर्स की व्यक्तिगत पहचान को दशार्ता है। वहीं, शाइन 125 लिमिटेड एडिशन एक क्लीन और टाइमलेस डिजाइन अप्रोच अपनाता है, जो मोटरसाइकिल के स्लीक स्कल्प्चर्ड फॉर्म और रिफाइंड लुक को उभारता है। इन नए एडिशन्स के साथ हमारा लक्ष्य राइडर्स को स्टाइल, कम्फर्ट और रोजमर्रा की भरोसेमंद परफॉर्मेंस का संतुलन देना है, ताकि वे सड़क पर आत्मविश्वास के साथ खुद को अभिव्यक्त कर सकें। दोनों मॉडल होंडा के सोच–समझकर किए गए डिजाइन और सभी के लिए सुरक्षित व सहज राइडिंग अनुभव पर फोकस को बरकरार रखते हैं।'

डियो 125 –एडिशनः

डियो 125 –एडिशन बॉडी पैनल्स पर दिए गए एक्सक्लूसिव –एडिशन ग्राफिक्स के साथ एक दमदार और नई पर्सनैलिटी को दशार्ता है, जो इसके सिलुएट को बोल्ड और यूथफुल एज देते हैं। साइबर ड्रिफ्ट थीम से प्रेरित इसका ड्यूल–टोन कलर स्कीम पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे के साथ पर्ल सायरन

ब्लू—स्कूटर को एनर्जेटिक स्टांस प्रदान करता है।

इसके स्पोर्टी अपील को और बढ़ाते हुए, –एडिशन में आकर्षक मैट फ्रैश कलर के कलर्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साइड्स पर मौजूद नए –एडिशन डेकल्स इसके ' फैक्टर' को हाईलाइट करते हैं, जो स्कूटर की एक्सप्रेसिव और इंडिपेंडेंट स्पिरिट को और मजबूत करते हैं। यह जेन` और युवा वर्किंग राइडर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, जो आत्मविश्वास और अपनी अलग पहचान को सड़क पर दिखाना चाहते हैं।

शाइन 125 लिमिटेड एडिशनः

शाइन 125 लिमिटेड एडिशन भारत की सबसे भरोसेमंद और सराही गई 125ू मोटरसाइकिलों में से एक की पहचान को आगे बढ़ाता है, जिसे अब एक मॉडर्न और मिनिमलिस्ट थीम के साथ नए रूप में पेश किया गया है। यह क्लीन सिम्प्लिसिटी की भावना को उभारते हुए मोटरसाइकिल को प्रीमियम, कम्फर्टेबल और रोजमर्रा के उपयोग के लिए आसान बनाता है।

शाइन 125 लिमिटेड एडिशन में नए प्रीमियम ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो मॉडल की आइकॉनिक पहचान को बनाए रखते हुए इसे एक अधिक रिफाइंड विजुअल कैरेक्टर देते हैं। पर्ल सायरन ब्लू कलर में उपलब्ध यह लिमिटेड एडिशन पाइराइट ब्राउन फिनिश अलॉय व्हील्स के साथ आता है, जो इसके टाइमलेस अपील में एक सॉफिस्टिकेटेड टच जोड़ते हैं। यह डिजाइन अप्रोच 'क्लीन सरफेस लुक' पर केंद्रित है, जो फंक्शनैलिटी और सादगी को दशार्ता है।

नया Dio 125 –Edition और Shine 125 Limited Edition फ्रेश, डायनामिक और प्रीमियम अपील देने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। इन नए एडिशन्स के साथ, HMSI देशभर के राइडर्स के लिए एक्सेसिबल और रिफाइंड मोबिलिटी ऑप्शन्स पेश करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहा है।

भारत के खिलाफ फेल हो गया अमेरिका का ऑयल ट्रैप! रूस के बयान ने व्हाइट हाउस में मचाई हलचल

(जीएनएस)।

रूस और भारत के बीच दशकों पुराने रिश्तों में दरार आने की अफवाहों पर रूस ने विराम लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने साफ कर दिया है कि भारत और रूस के बीच एनर्जी पार्टनरशिप (ऊर्जा सहयोग) को लेकर भारत का रुख बदलने का कोई कारण नहीं दिखता।

जखारोवा ने कहा कि रूस से संसाधनों का व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है।

'भारत कोई नया खरीदार नहीं'

इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि रूस भारत के लिए एकमात्र तेल आपूर्तिकर्ता नहीं है और भारत हमेशा से अन्य देशों से भी तेल खरीदता रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यापारिक रिश्ते में कुछ भी 'नया' नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य और लाभकारी प्रक्रिया है।

रूस के इन बयानों के बीच भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में देश की रणनीति साफ की। उन्होंने कहा कि, 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और बाजार की स्थिति को देखते हुए अपने एनर्जी सोर्स में विविधता लाना हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है।'

यह बयान ऐसे समय में आए हैं जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका में हैं और वहां के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर ने अमेरिका में इंडो–पैसिफिक, पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

हालांकि जयशंकर अमेरिका के साथ खनिज सुरक्षा और 'FORGE' पहल पर सहयोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूस का यह बयान स्पष्ट करता है कि भारत ने 'ऑयल गेम' में अपने पुराने मित्र का साथ छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है।

एक सवाल के जवाब में कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

ऑब्जेक्टिव मार्केट की स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल को ध्यान में रखते हुए अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई करना इसे सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है।

टैरिफ घटने से चावल, मसाले और टेक्सटाइल निर्यात को मिलेगा बल, कपास किसानों की आय बढ़ेगी

(जीएनएस)।

भारत–यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे भ्रामक आरोपों के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते में भारतीय कृषि, विशेषकर कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह डील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का नया उदाहरण है और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से साफ कर दिया था कि किसान हित सर्वोपरि हैं।

दिल्ली में आज मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे मुख्य अनाज, फल, प्रमुख फसलें, मिलेट्स और डेयरी उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं और भारतीय कृषि या डेयरी पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित पूरी तरह संरक्षित हैं और इस समझौते से उल्टा भारत के किसानों को नए अवसर मिलेंगे।

छोटे किसानों की चिंता और यूएस फार्म प्रोडक्ट्स पर स्थिति स्पष्ट

इस आशंका पर कि देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और छोटे किसानों पर असर पड़ सकता है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोई 'बड़ी चीज' भारत के बाजार में अचानक नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सभी मुख्य फसलें, मुख्य अनाज, फल और डेयरी उत्पाद सुरक्षित हैं और किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए बाजार नहीं खोला गया है, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह हो सके।

यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के उस ट्वीट से पैदा संशय पर, जिसमें अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स के ज्यादा भारत आने की बात कही गई थी, श्री चौहान ने कहा कि वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने संसद में पूरे तथ्य स्पष्ट कर दिए हैं और वे स्वयं भी दोहरा रहे हैं कि छोटे और बड़े, सभी भारतीय किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और मुख्य कृषि उत्पादों के लिए बाजार इस प्रकार नहीं खोला गया है कि किसानों पर दबाव बने।

चावल, मसाले और टेक्सटाइल निर्यात को नया बल

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि भारत पहले से ही अमेरिका सहित विभिन्न देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है और हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 63,000 करोड़ रुपये के चावल का निर्यात किया गया था।

उन्होंने कहा कि टैरिफ कम होने से हमारे चावल, मसालों और टेक्सटाइल के निर्यात को बल मिलेगा और जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका सीधा लाभ कपास उगाने वाले हमारे किसानों को होगा। श्री चौहान ने कहा कि यह समझौता समग्र रूप से भारत के किसानों के हित में है और विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने के बावजूद तथ्य यही हैं कि किसान हित सुरक्षित हैं और निर्यात के नए अवसर खुल रहे हैं।

अगर विपक्ष बोलने ही नहीं देगा तो समझाया कैसे जाएगा'

जब यह सवाल उठा कि विपक्ष कह रहा है कि अगर ट्रेड डील कर रहे हैं तो सरकार आकर फाइन प्रिंट को संसद और देश के सामने समझाए, तो कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दोहराया कि डील की सारी डिटेल्स समय पर सामने आएंगी, लेकिन उसका मूल साफ है – किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

किसान अन्नदाता, किसानों की सेवा भगवान की पूजा

कृषि मंत्री ने चिंता जताई कि कृषि का क्षेत्र इतना बड़ा है कि किसी भी तरह की अफवाह से किसानों में अनावश्यक चिंता और बेचैनी पैदा हो सकती है, इसलिए सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन देना जरूरी है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

9वां परीक्षा पे चर्चा 6 फरवरी, 2026 को आयोजित किया जाएगा

परीक्षा पे चर्चा राष्ट्रव्यापी स्तर पर कई स्थानों पर आयोजित होने वाला पहला कार्यक्रम है

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का छात्रों के साथ अनूठा संवादात्मक कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी), अपने शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे परीक्षा के तनाव पर चर्चा करने और परीक्षाओं को एक उत्सव और जीवन के अभिन्न अंग के रूप में मनाने के लिए वापस आ रहा है। यह परीक्षा पे चर्चा का 9वां आयोजन होगा।

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन (डीडी) और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वेव्स ओटीटी, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो, जी5, सोनी लिव और स्पॉटिफाई (ऑडियो प्लेटफॉर्म) जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी 'परीक्षा पे चर्चा' का लाइव प्रसारण होगा।

एनईपी 2020 के अनुरूप, पीपीसी की अवधारणा का उद्देश्य छात्रों के परीक्षा के अनुभव को नया रूप देना है, ताकि उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिले और परीक्षा के अवसर को उत्सव के रूप में मनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने अपने विचारों को अपनी पुस्तक "एग्जाम वॉरियर्स" में संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जो कई भाषाओं और ब्रेल में उपलब्ध है। इसमें उन्होंने आत्मविश्वास पर बल दिया है और इन मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि हमारे बच्चों को वह आनंदमय बचपन मिल सके जिसके वे हकदार हैं।

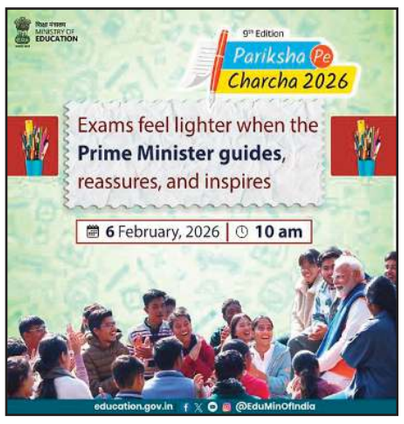

प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित, परीक्षा पे चर्चा एक सशक्त और नवोन्मेषी पहल है, जो हर साल नए-नए तथ्य पेश करती है। पहली बार, पीपीसी 2026 का आयोजन देश के सभी हिस्सों को कवर करते हुए कई स्थानों पर किया गया। दिल्ली के अलावा, पीपीसी 2026 का आयोजन तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देव मोगरा और असम के गुवाहाटी सहित चार अलग-अलग स्थानों पर किया गया, जिसमें देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग शामिल थे।

परीक्षा पे चर्चा 2026 के आयोजन की तैयारियों के तहत, देशभर के विद्यालयों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए छात्रों द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ और पराक्रम दिवस पर चिन्हित केंद्रीय विद्यालयों में आयोजित प्रश्नोत्तरी और लेखन प्रतियोगिताएं शामिल थीं।

सराफा व्यवसायी के घर और दुकान पर आयकर विभाग ने मारा छापा : वृंदावन में आरएस ज्वैलर्स पर छापे के बाद बाजार में मचा रहा हड़कंप

मथुरा (जीएनएस)। धार्मिक नगरी वृंदावन में सरार्फा कारोबारी की दुकान और मकान पर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज की टीम ने संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की है। वृंदावन में कैला देवी मंदिर के पास आरएस ज्वेलर्स पर छापामार कार्रवाई से अन्य व्यापारियों में हड़कम्प मचा रहा। जानकारी के अनुसार सीजीएसटी विभाग को काफी समय से टैक्स चोरी और स्टॉक में हेराफेरी की सूचनाएं मिल रही थीं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीजीएसटी और सेन्ट्रल एक्साइज की टीम ने योजना तैयार करके संयुक्त रूप से सरार्फा कारोबारी की दुकान और मकान पर एक साथ छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। छापामार कार्रवाई शुरू होते ही कारोबारी की दुकान और मकान के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। इस बीच टीम ने किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने दिया। छापामार कार्रवाई के दौरान सीजीएसटी और सेन्ट्रल एक्साइज टीम के अधिकारियों ने दुकान में मिले सोने-चांदी के स्टॉक का बिलों से मिलान किया। इसके साथ ही पिछले कई वर्षों के खरीद एवं बिक्री के दस्तावेज, बैंक लेन-देन का विवरण तथा कच्चे बिलों की पड़ताल की। किंतु सीजीएसटी और सेन्ट्रल एक्साइज की टीम ने किसी भी प्रकार की आधिकारिक बरामदगी की पुष्टि नहीं की गई है। फिर माना जा रहा है कि जांच में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। छापामार कार्रवाई की खबर फैलते ही सरार्फा बाजार के कारोबारियों में हड़कम्प की स्थिति बनी रहा। जिस सरार्फा कारोबारी के प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई की गई है, उसका नाम शरद सर्राफ बताया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक सीजीएसटी और सेन्ट्रल एक्साइज की टीम की कार्रवाई चल रही थी।

कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया सीवेज प्लांट का निरीक्षण : प्लांट पड़ा बंद, मृत पड़े मिले पशु और गंदगी का मिला अंबार

-कांग्रेसियों ने प्रशासन को दी चेतावनी, यमुना की दुर्दशा नहीं सुधारी तो होगा आंदोलन

मथुरा (जीएनएस)। कांग्रेस महानगर कमेटी के अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने कांग्रेसियों के साथ मसानी नाले के पास स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को देखने पहुंचे। कांग्रेसियों को वहां पर ब्रज हालात बेहद खराब हालत मिली। कांग्रेस पदाधिकारियों को निरीक्षण में एसटीपी प्लांट पूरी तरह जर्जर और निष्क्रिय अवस्था में मिला। प्लांट का संचालन लगभग ठप पाया गया, जिसके चलते मसानी नाले की गंदगी बिना किसी शोधन के सीधे यमुना में गिर रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस प्लांट का फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, यह केवल कागजों में ही चल रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान नाले और एसटीपी प्लांट के आस-पास 5-6 मृत पशु पड़े हुए मिले हैं। कांग्रेसियों ने मृत पशु और गंदगी की फोटो और वीडियो बना लिए। कांग्रेसियों ने आशंका व्यक्त की है कि नाले के अंदर तथा आस-पास और भी मृत पशु मिल सकते हैं, जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रही है, बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही के चलते यमुना को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। इस संबंध में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि यह स्थिति भाजपा की असंवेदनशील और यमुना विरोधी नीति को उजागर कर रही है। कहा कि एक ओर आस्था की बात की जाती है और दूसरी ओर नगर निगम तथा प्रशासन की लापरवाही से यमुना में गंदगी और मृत पशु पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है। कहा कि यमुना प्रदूषण, मृत पशुओं की दुर्दशा और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए नगर निगम, मेयर और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर जल्द ही एसटीपी प्लांट को दुरुस्त करके नालों की गंदगी नहीं रोका गई और मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आंदोलन करेगी। इस दौरान आनंद शर्मा, राहुल चतुर्वेदी, शिवकुमार गौतम (बंटी), निशांत शर्मा और महेश छत्रवेदी समेत अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।

कृष्णा कॉलेज में खेल सप्ताह 'कृष्ण रंग' का सफल आयोजन

लखनऊ। कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एवं कृष्णा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के परिसर में वार्षिक खेल सप्ताह 'कृष्ण रंग' का शुभारंभ दिनांक 28इँ जनवरी 2026 को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी मोहनलालगंज, श्री विकास कुमार पांडेय उपस्थित रहे।

यह खेल सप्ताह सात दिनों तक चला, जिसके उपरांत महाविद्यालय परिसर में ही समापन समारोह का आयोजन किया गया, तत्पश्चात इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। इस अवसर पर श्री अजय कुमार त्रिपाठी (सेवानिवृत्त आर टी वो.) एवं श्रीमती स्मिता त्रिपाठी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर डॉ. अनुराग चतुर्वेदी (निदेशक, के सी ई एम), डॉ. तेजल जी चतुर्वेदी (निदेशक, के एन पी आई), प्राचार्य डॉ. नीरज कुमार श्रीवास्तव (के सी ई एम), प्राचार्य प्रो. जेनी डी (के एन पी आई), वाइस प्रिंसिपल प्रो. अनुराग चौहान (ड्ठढक), गेम इंचार्ज डॉ. ब्रह्मवेश कुमार एवं श्री ओमप्रकाश सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न (मोमेंटो) भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप पदक (टीँ'२) एवं शील्ड प्रदान की गई। खेल सप्ताह में रेड हाउस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हाउस ट्रॉफी प्राप्त की।

खेल सप्ताह के प्रथम दिन 100 मीटर दौड़, सेक रेस, शॉट पुट, थ्री-लेग रेस एवं लेमन स्पून रेस जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने शानदार जोश एवं ऊर्जा का प्रदर्शन किया। द्वितीय दिन वॉलीबॉल, खो-खो, डॉज बॉल, शतरंज, कैरम तथा शॉट पुट जैसी इनडोर एवं आउटडोर प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी शक्ति, रणनीति और एकाग्रता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

तृतीय दिन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, फुटबॉल, थ्री-बॉल के साथ-साथ पॉट पेंटिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे खेल के साथ-साथ विद्यार्थियों की रचनात्मकता को भी मंच मिला। चतुर्थ दिन कबड्डी, टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, डॉज बॉल, लॉन्ग जंप एवं म्यूज़िकल चेयर जैसी रोमांचक प्रतियोगिताओं ने पूरे वातावरण को उत्साह से भर दिया।

इस खेल सप्ताह की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि कई विद्यार्थियों ने एक से अधिक खेलों में जीत हासिल कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। विशेष रूप से मानवेंद्र, अखिलेश प्रताप सिंह, शमिला, लक्ष्मी धुरिया, एकता चौरसिया, राधिका पांडेय एवं निधि विक्रम जैसे विद्यार्थियों का प्रदर्शन अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत रहा।

इस अवसर पर समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खेल सप्ताह के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉ. नीरज कुमार श्रीवास्तव (के ई सी एम) द्वारा प्रस्तुत किया गया।

नानपारा में अवैध कब्जों के विरूद्ध जारी है ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

एसडीएम के नेतृत्व में सरकारी भूमि पर बने अस्थायी कब्जों को कराया गया जमीदोज

ब्यूरो रिपोर्ट इसराइल खान

बहराइच 05 फरवरी। नानपारा तहसील क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामनगर गुलरिया, हरिहरपुर पुरैना व जलालपुर स्थित गाटा संख्या 551 रकबा 0.006 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 470 रकबा 0.10 हेक्टेयर जोकि राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के नाम दर्ज है तथा गाटा संख्या 122 रकवा 0.099 हेक्टेयर खलिहान व गाटा संख्या 766 रकवा 0.034 हेक्टेयर पर ग्राम के ही कुल 06 व्यक्तियों के द्वारा लंबे समय

से सरकारी भूमि पर अस्थाई टीन शेड व झोपड़ी डालकर किये गये अवैध कब्जे को उपजिलाधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी के निर्देश पर नायब तहसीलदार नबाबगंज अक्षय पांडेय, राजस्व निरीक्षक मिश्रीलाल पाल व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा एसएसबी व पुलिस की मदद से हटवा दिया गया। अवैध कब्जों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से अवैध कब्जेदारों के हौसले पस्त होते दिखायी दे रहे हैं। तहसील प्रशासन की सख्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश क्षेत्र में गया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसील प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही से आमजन में यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि वर्तमान प्रशासन अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध पूरी दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है,

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 172 स्टेशनों का काम पूरा हुआ : श्री अश्विनी वैष्णव

(जीएनएस)।

स्टेशन का पुनर्विकास

रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के दीर्घकालिक पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत स्टेशनों के सुधार हेतु मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका कार्यान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लान में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- स्टेशन और आवागमन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों हिस्सों से जुड़ाव
- स्टेशन भवन का सुधार
- प्रतीक्षा कक्षों, शौचालयों, बैठने की व्यवस्था और पानी के बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े फुट ओवरब्रिज/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान।
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप की व्यवस्था
- प्लेटफार्म की सतह में सुधार/उपलब्धता और प्लेटफार्म के ऊपर आवरण का प्रावधान
- 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था करना।
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकतानुसार एग्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्धारित स्थान, हरियाली आदि की व्यवस्था करना।

इस योजना में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार बैलास्टलेस ट्रैक का प्रावधान, चरणबद्ध कार्यान्वयन और व्यवहार्यता के साथ-साथ दीर्घकालिक रूप से स्टेशन पर शहर केंद्र का निर्माण जैसी परिकल्पनाएं भी शामिल हैं। अब तक इस योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। फिलहाल, 172

स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है।

पुलों की सुरक्षा

भारतीय रेलवे (आईआर) द्वारा देशभर के पुलों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आईआर में रेलवे पुलों के निरीक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है। सभी पुलों का निरीक्षण वर्ष में दो बार नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है, एक बार मानसून शुरू होने से पहले और एक बार मानसून के बाद विस्तृत निरीक्षण। इसके अतिरिक्त, मुख्य पुल अभियंता (सीबीई) द्वारा निर्धारित स्थिति के आधार पर कुछ पुलों का निरीक्षण अधिक बार भी किया जाता है। महत्वपूर्ण और बड़े पुलों का व्यापक तकनीकी निरीक्षण इस प्रकार किया जाता है कि ऐसे 20 प्रतिशत पुलों का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है।

पुलों की मरम्मत/मजबूतीकरण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और यह पुलों के निरीक्षण के आधार पर की जाती है। 2022-2025 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, भारतीय रेलवे में 8,626 रेलवे पुलों की मरम्मत/पुनर्वास/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ रेलवे पुलों की स्थिति के आधार पर उनका निरीक्षण अधिक बार किया जाता है। रेलवे पुलों की मरम्मत/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और निरीक्षण के दौरान उनकी भौतिक स्थिति के आधार पर आवश्यकतानुसार की जाती है। विशेष तकनीकी ऑडिट भी किया जाता है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। सबवे/आरयूबी का निरीक्षण मानसून शुरू होने से पहले और बाद में किया जाता है। रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) और सबवे में जलभराव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि नए डिजाइनों में बेहतर जल निकासी व्यवस्था, पानी को प्राकृतिक नालियों में मोड़ना, हंप और क्रॉस-ड्रेन बनाना, जोड़ों को सील करना और संवेदनशील स्थानों पर उच्च क्षमता वाले पंप लगाना।

भारतीय रेलवे पुल नियमावली (आईआरबीएम) में पुल पुनर्निर्माण कार्यों की कार्यप्रणाली दी गई है। अनुबंध प्रबंधन और अनुबंध की सामान्य एवं विशेष शर्तों के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएपी) और निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (आईटीपी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

निष्पादन एजेंसी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दोष दायित्व अवधि तक सुरक्षा जमा राशि को रोके रखने और अनुबंध समाप्त करने जैसे दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है। पुल निर्माण कार्य का पूरा होना स्थान, प्रकार, योजनाओं की स्वीकृति, पहुंच मार्ग की उपलब्धता, जलवायु परिस्थितियों के कारण वर्ष में कार्य मौसम की अवधि, ब्लॉकों की उपलब्धता, गति प्रतिबंध आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

कोच निर्माण

वर्तमान में, रेल मंत्रालय के अधीन देश में तीन कोच निर्माण इकाइयां कार्यरत हैं। कोच निर्माण इकाइयों के विकास की लागत स्थान, निर्मित किए जाने वाले कोचों के प्रकार, नियोजित उत्पादन क्षमता और स्थापित की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र जैसे कारकों पर निर्भर करती है। कोच निर्माण इकाइयों के विकास पर व्यय लंबी अवधि में और कई चरणों में होता है, जिसमें इकाइयों की प्रारंभिक स्थापना के साथ-साथ समय-समय पर सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार भी शामिल है। उदाहरण के लिए, रायबरेली स्थित नवीनतम कार्यरत कोच निर्माण इकाई - मॉडर्न कोच फैक्ट्री - की स्थापना पर 3,042.83 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

इसके अतिरिक्त, तीन कार्यरत कोच निर्माण इकाइयों, अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली के उन्नयन/विस्तार से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2443 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

एलएचबी कोच

एलएचबी कोचों के बढ़ते उपयोग के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि आईसीएफ कोचों को अधिक सुरक्षित और आधुनिक एलएचबी कोचों से बदलने का कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। तकनीकी रूप से उन्नत एलएचबी कोचों में बेहतर सवारी, बेहतर सौंदर्य और हल्के वजन का डिजाइन, चढ़ाई रोधी विशेषताएं, विफलता संकेत प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन (सेकेंडरी), स्टेनलेस स्टील का ढांचा और डिस्क ब्रेक प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं।

मस्जिद बुतूली बेगम व इमामबाड़ा औनो मोहम्मद का भव्य इफ़्तिताह

मौलाना कल्बे जवाद ने की फातिहा ख्वानी

लखनऊ। वजीरबाग रोड स्थित रुस्तमनगर में जश्न-ए-इमामे अस्र के मुबारक मौके पर एक भव्य रूहानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मस्जिद बुतूली बेगम और इमामबाड़ा जनाबे औनो मोहम्मद (अ.स.) का इफ़्तिताह व नज़्र का आयोजन पूरी अकीदत के साथ संपन्न हुआ।

इस मुकद्दस मौके पर शहर के मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना कल्बे जवाद साहब ने शिरकत की। उन्होंने मस्जिद और इमामबाड़े के उद्घाटन के साथ ही विशेष नज़्र की फातिहा ख्वानी कराई। इस दौरान इमाम-ए-जमाना

और शोहदा-ए-कर्बला की बारगाह में नजराना-ए-अकीदत पेश किया गया।

कार्यक्रम में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद फिरोज अब्बास नकवी कुम्मी ने महफिले फजाइल को संबोधित किया और इमाम की शान में बयान पढ़े। कार्यक्रम की निजामत मशहूर नाजिम जनाब नय्यर मजीदी साहब ने की।

इस रूहानी महफिल में कई नामचीन हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिनमें मुख्य रूप से तिलावत, जनाब कारी हसन आबिद साहब और जनाब हसन फराज साहब आलिम, जनाब मौलाना दानिश जैदी साहब शायर, जनाब फरमान लखनवी साहब, अन्य जनाब फुरकान हुसैन, रिजवान रिजवी, फैजान जाफर और अयान अमीर।

कार्यक्रम के अंत में कन्वीनर जनाब फरमान लखनवी और सैयद इफ़्तिखार हुसैन रिजवी मीसम ने तमाम मोमिनीन और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पूरे वजीरबाग इलाके में जश्न का माहौल रहा और बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की।

सोनालीका ने एफ '26 के 10 महीनों में 1.51 लाख ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे तेज बिक्री के साथ शानदार बिक्री प्रदर्शन दर्ज किया

सोनालीका ने F '26 के 10 महीनों में 1.51 लाख ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे तेज बिक्री के साथ शानदार बिक्री प्रदर्शन दर्ज किया

लखनऊ, 5 फरवरी 2026: 30वें वर्षगाँठ की शानदार शुरूआत करते हुए, भारत से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट में नंबर 1 ब्रांड सोनालीका ट्रैक्टर्स ने अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के 10 महीनों के दौरान 1,51,604 ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे तेज कुल बिक्री दर्ज की है। भविष्य के लिए तैयार तकनीकों से लैस हैवी-ड्यूटी ट्रैक्टरों द्वारा सोनालीका ने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि समृद्धि का नेतृत्व करना जारी रखा है और यह बदलते कृषि परिदृश्य में निरंतर वृद्धि देने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है। सोनालीका ने हाल ही में अपने उद्देश्य 'जीतने का दम' को दोहराया है, जो पूरे देश में ब्रांड को मजबूत करने के कार्यक्रम का हिस्सा है और इसकी तेज विकास रणनीति को दर्शाता है।

महज 30 वर्षों में, सोनालीका एक छोटे शहर की कंपनी से बढ़ कर भारत से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट में नंबर 1 ब्रांड और देश में तीसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर ब्रांड बन गया है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसने पांचवे सबसे बड़े ट्रैक्टर ब्रांड के रूप में स्थान हासिल किया है । सोनालीका के हैवी-ड्यूटी ट्रैक्टर किसानों द्वारा स्थाई विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश माने जाते हैं,

क्यूंकि कंपनी की प्रगतिशील यात्रा मजबूत सिद्धांतों पर आधारित है जिनमें किफायती इंजीनियरिंग, बेहतर उत्पादन क्षमता और किसानों को प्राथमिकता देना शामिल है।

जीएसटी कटौती द्वारा किसानों को बेहतर पूवार्नुमान और भरोसा मिला है एवं वह सशक्त महसूस कर रहे हैं जिससे साथ ही मशीनीकरण को भी बढ़ावा मिला है। सोनालीका अपने विश्व के सबसे बड़े एकीकृत ट्रैक्टर निर्माण प्लांट में किसानों के भविष्य के लिए तैयार समाधानों को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और भारत की आर्थिक प्रगति में कृषि की भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके।

इस नई उपलब्धि पर अपने विचार साझा करते हुए, श्री रमन मित्तल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ने कहा, 'अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच 10 महीनों में 1.51 लाख ट्रैक्टरों की बिक्री का अब तक का सबसे तेज आंकड़ा दर्ज करके हम बेहद प्रसन्न हैं। इससे हमें 2026 में अपने 30वीं वर्षगाँठ के लिए एक मजबूत्त शुरूआत मिली है। यह हमारे इस सरल विश्वास की पुष्टि करता है कि निरंतर विकास मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होता है और हमारे ब्रांड पर किसानों का भरोसा एक स्पष्ट प्रमाण है। इंजीनियरिंग से लेकर अमल करने तक हम जो भी निर्णय लेते हैं, उससे हम सुनिश्चित करते हैं कि किसान के खेतों में ज्यादा उत्पादकता, भरोसा और बेहतर मूल्य प्राप्त हो।'

इस मौसम में रबी की बुआई शानदार रही है, जिससे अच्छी फसल की उम्मीदें बढ़ गई हैं और किसानों को हमारे ईंधन-कुशल, आरामदायक और ताकतवर ट्रैक्टरों का लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। कृषि और सम्बंधित क्षेत्रों के लिए हाल ही में किए गए बजट आवंटन से जमीनी स्तर पर कृषि परिवर्तन के प्रति स्थायी नीतिगत प्रतिबद्धता को बल मिलता है, जबकि जीएसटी सुधार दीर्घकालिक रूप से अधिक उत्पादकता लाएंगे, किसानों के मनोबल को बढ़ाएंगे और मशीनीकरण को गति देंगे। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था उत्पादकता और निवेश के स्तंभों पर आगे बढ़ रही है, हम 'जीतने का दम' द्वारा संचालित विश्वसनीय, भविष्य के लिए तैयार तकनीक के साथ किसानों का समर्थन करने के स्पष्ट इरादे से कृषि को दम, विस्तार और क्षमता के साथ ताकत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नूरजहाँ गर्ल्स हायर सेकेंड्री व शाहीन किड्स प्वाइंट में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन

लखनऊ, 05 फरवरी 2026।

नूरजहाँ गर्ल्स हायर सेकेंड्री एवं शाहीन किड्स प्वाइंट (इडेन पब्लिक स्कूल) में गुरुवार को वार्षिक उत्सव के अवसर पर भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शाहीन कौसर, अतिथि डॉ. नाजिया मैनन, विद्यालय के प्रबंधक/संस्थापक श्री परवेज आलम सिद्दीकी (भुट्टो) तथा प्रधानाचार्य शेख नजरूल इस्लाम ने फीता काटकर किया।

इस अवसर पर नूरजहाँ गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्या मदीना बानो, शाहीन किड्स की इंचार्ज उम्मे जरीन, सभी अध्यापिकाएं एवं हजारों की संख्या में महिला अभिभावक उपस्थित रहे।

विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत, नृत्य-नाटक तथा भारत की अखंडता और एकता को दर्शाते हुए विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। छोटे-छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उत्साह और उल्लास से भर दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक एवं संस्थापक श्री परवेज आलम भुट्टो ने कहा कि वार्षिक उत्सव विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को निखारने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अध्यापिकाओं और अभिभावकों के सहयोग की सराहना की।

अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और पूरा परिसर उत्साह, उल्लास एवं प्रेरणा से ओतप्रोत नजर आया

लखनऊः अब सड़कों पर नहीं ठहरेंगी ई सिटी बसें, आठ रूटों पर 40 स्टॉपेज हुए तय; नोट कर लीजिए स्टेशनों के नाम

लखनऊ , (जीएनएस)। लखनऊ की ई सिटी बसें अब कहीं भी नहीं रुक सकेंगी। शहर के अंदर इनके स्टॉपेज तय कर दिए गए हैं। यह आदेश आठ रूटों के लिए तय हुए हैं।

लखनऊ की सड़कों पर दौड़ रहीं सिटी बसों के ठहराव अब सड़कों पर नहीं, बल्कि 40 स्टॉपेजों पर ही होंगे। आठ रूटों की बसों के लिए स्टॉपेज पर बस रोकने के निर्देश सिटी ट्रांसपोर्ट के नए प्रबंध निदेशक ने बुधवार को दिए हैं।

पदभार ग्रहण करते ही प्रबंध निदेशक अमरनाथ सहाय ने सड़कों पर दौड़ रही सिटी बसों के ठहराव के लिए सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सिटी बसें अब बस शेल्टर पर ही मिलेंगी। जहां बसों के आवागमन के लिए जल्द ही समयसारिणी भी लगा दी जाएगी। इस संबंध में डिपो इंचार्ज से लेकर बस ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया गया हैं।

अभी तक सिटी बसें सड़कों पर जहां-तहां रोक दी जा रही हैं, जिससे यात्री स्टॉपेज पर बसों का इंतजार करते हैं और बसें सड़कों पर जाम का

कारण भी बन जाती हैं। इस समस्या को निस्तारित करने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया गया है, जिसे हफ्तेभर में दोबारा निरीक्षण के दौरान चेक भी किया जाएगा। बता दें कि लखनऊ में 115 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन हो रहा है। इनसे प्रतिदिन 10 से 12 हजार यात्री सफर करते हैं।

यहां रुकेंगी इलेक्ट्रिक सिटी बसें

आलमबाग मेट्रो स्टेशन, मवईया, टेढ़ीपुलिया, अवध चौराहा, अमौसी मेट्रो, पारा चौकी, चारबाग स्टेशन दोनों ओर, पॉलिटेक्निक चौराहा वेव सिनेमा के सामने, सहारा बाजार के सामने, फन मॉल, शहीद स्मारक, हैनीमैन चौराहा, रजनीखंड, स्मृति उपवन, बाराबिरवा, मंत्री आवास, दयाल चौराहा, नादरगंज, अलीगंज आदि मार्गो पर सिटी बसों के स्टॉपेज तय किए गए हैं।

इन आठ रूटों की बसों के स्टॉपेज तय

-चौक घंटाकर से नैमिषारण्य
-ट्रांसपोर्टनगर से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा
-शकुंतला विवि से जीपीओ
-बालागंज से कमता बस स्टेशन
-ट्रांसपोर्टनगर से टेढ़ीपुलिया
-सरोजनीनगर से कमता बस स्टेशन
-राजाजीपुरम से देवा रोड अपट्रान
-बालागंज से जीपीओ हजरतगंज

तय किए गए हैं 40 शेल्टर

लखनऊ में सिटी बसों के ठहराव के लिए 40 शेल्टर तय किए गए हैं। इस संबंध में चालक-परिचालकों को निर्देश दिए हैं। ताकि बस स्टॉपेज पर ही रोकी जाएं, न कि सड़कों पर। इससे जाम की स्थिति से राहत मिलेगी और यात्रियों को भी सुविधा हो जाएगी।-अमरनाथ सहाय, प्रबंध निदेशक, सिटी ट्रांसपोर्ट

सऊदी अरब : इंसानों के साथ-साथ ऊंटों को भी मिलेगा पासपोर्ट

सऊदी अरब ने ऊंटों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट जारी करने की योजना बनाई है। यह फैसला इस बात को दिखाता है कि सऊदी संस्कृति और अर्थव्यवस्था में ऊंटों की कितनी अहम भूमिका है। देश का पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय इस पहल के जरिए ऊंटों की आबादी को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहता है। इसका मकसद एक भरोसेमंद राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, जिससे ऊंट पालन से जुड़ी उत्पादकता और कार्यक्षमता दोनों को बढ़ाया जा सके। मंत्रालय ने इस हरे रंग के पासपोर्ट की तस्वीरें भी साझा की हैं, जिन पर सऊदी अरब का राजकीय प्रतीक और सुनहरे रंग का ऊंट बना हुआ है।

बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को आसान बनाएगा ऊंट पासपोर्ट

सरकारी प्रसारक अल अखबारिया के मुताबिक, यह पासपोर्ट ऊंटों के व्यापार और उनके परिवहन को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह दस्तावेज ऊंट मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और स्वामित्व साबित करना भी आसान बनाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 तक सऊदी अरब में करीब 22 लाख ऊंट मौजूद

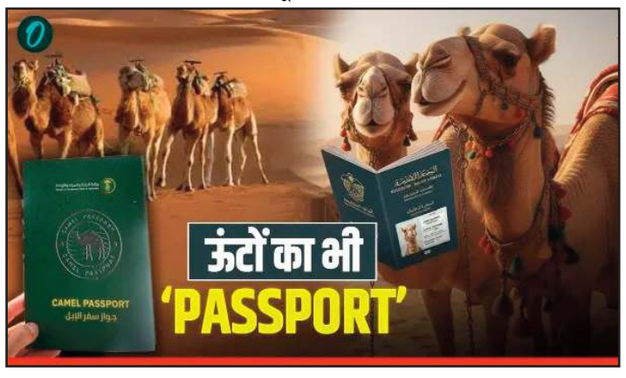

हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए यह पहल और भी ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक मानी जा रही है।

अरब संस्कृति में ऊंटों की सदियों पुरानी अहमियत

अरब प्रायद्वीप में ऊंटों का महत्व सदियों पुराना है। ये सिर्फ परिवहन का साधन नहीं रहे, बल्कि धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक रुतबे का भी प्रतीक माने जाते रहे हैं। आज भी ऊंट एक तेजी से बढ़ते प्रजनन उद्योग का हिस्सा हैं और हर साल होने वाली ऊंट सौंदर्य प्रतियोगिताओं का केंद्र रहते हैं। इन प्रतियोगिताओं में कई बेशकीमती ऊंट लाखों डॉलर में बिकते हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अधिकारियों ने ऊंटों के होंठ और कूबड़ बदलने जैसी अवैध कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं पर भी रोक लगाई है, क्योंकि इन्हें प्राकृतिक सौंदर्य के खिलाफ माना गया है।

7,000 साल पुरानी नक्काशी

साल 2021 में प्रकाशित एक शोध में सामने आया कि सऊदी अरब में मिली 7,000 साल पुरानी ऊंटों की नक्काशी इस जानवर के साथ देश के गहरे ऐतिहासिक रिश्ते को साबित करती है। समाचार एजेंसी अनादोलु के अनुसार, ऊंटों के लिए जारी किया जाने वाला यह पासपोर्ट एक व्यापक पहचान दस्तावेज होगा। इसमें माइक्रोचिप नंबर, नाम, जन्मतिथि, नस्ल, लिंग, रंग, जन्म स्थान, पासपोर्ट जारी करने की तारीख और स्थान जैसी पूरी जानकारी शामिल होगी। इसके साथ ही ऊंट की पहचान के लिए दोनों तरफ की साफ तस्वीरें भी पासपोर्ट में लगाई जाएंगी।

टीकाकरण रिकॉर्ड और डॉक्टर की पुष्टि भी होगी दर्ज

इस ऊंट पासपोर्ट में एक अलग से टीकाकरण तालिका भी होगी, जिसमें पशु चिकित्सा से जुड़े सभी टीकों का रिकॉर्ड साफ-साफ दर्ज किया जाएगा। इन रिकॉर्ड्स की पुष्टि पशु चिकित्सक के नाम, हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर से की जाएगी। अनौपचारिक आंकड़ों के मुताबिक, सऊदी अरब में लगभग 80,000 ऊंट मालिक हैं। इसी वजह से सऊदी अरब को दुनिया के प्रमुख ऊंट-मालिक देशों में गिना जाता है।

लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी रायबरेली में डिरेल होने से बची, ट्रेन के इंजन में फंसी साइकिल

(जीएनएस)।

लखनऊ वाराणसी जा रही इंटरसिटी ट्रेन गुरुवार को रायबरेली में डिरेल होने से बच गई। अचानक से रुकी ट्रेन की वजह से लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारी ने हालात को संभाल लिया।

रायबरेलीः लखनऊ-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस रायबरेली के रूपामऊं रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह हादसे का शिकार होने बच गई। सूचना मिलते ही आनन-फानन में रेलवे अधिकारी और टीम मौके पर पहुंची। साइकिल को अलग करने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया।

इंटरसिटी एक्सप्रेस गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे रायबरेली के रूपामऊं रेलवे स्टेशन के पास रेलवे

गेट नंबर 143 के समीप ट्रैक पर साइकिल की वजह से ट्रैक से उतरते-उतरते बच गई। इंटरसिटी के इंजन में साइकिल फंस गई। लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन डिरेल होने से बच गई। लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। अचानक से ट्रेन के रुकने से यात्रियों में अफरा-मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और इंजीनियर टीम मौके पर पहुंची व हालात को संभाला। किसी भी तरह की अफरा-तफरी नहीं मचने पाई।

काफी मशक्कत के बाद इंजन में फंसी साइकिल को निकाला गया। इसके बाद लखनऊ से वाराणसी जा रही इंटरसिटी को रवाना किया गया। वहीं, इस मामले में आरपीएफ ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के दौरान घटनास्थल पर सक्रिय मोबाइल नंबरों को टैक किया जा रहा है। साथ ही जांच की जा रही है कि रेलवे ट्रैक पर साइकिल कहां से आ गई।

लखनऊ में मौसी ने भतीजे को ठगा, नौकरी के नाम पर लिए 90 लाख रुपये, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर धमकी भी दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

लखनऊ : (जीएनएस)। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में ठेका और नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 90 लाख की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. सगी मौसी और मौसेरे भाई ने मिलकर पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया. हजरतगंज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के निर्देश पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पीड़ित राहिल निवासी बारूदखाना, अमीनाबाद ने बताया, 2023 में मौसी सुमायरा ने अपने बेटे अब्दुल्ला की फर्म अरबाज ग्लोबल

पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए उकसाया. अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच 70 लाख रुपये नकद और 20 लाख रुपये बैंक खाते के माध्यम से ट्रांसफर किए. मोटी रकम लेने के बाद न तो मुनाफे में कोई हिस्सा दिया गया और न ही पैसे वापस किए गए.

एलडीए में फर्जी नौकरी और ठेके का झांसा : पैसे वापस मांगने पर विवाद बढ़ा तो मौसी ने नया जाल बिछाया. राहिल को एलडीए में बड़ा ठेका दिलाने का झूठा आश्वासन दिया गया. इसके बाद मौसी ने राहिल को एलडीए में लिपिक पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और उसके दस्तावेज ले लिए. सुमायरा ने राहिल को एक नियुक्ति पत्र सौंपा, लेकिन जब राहिल उसे लेकर एलडीए कार्यालय पहुंचा, तो पता चला कि वह पत्र और हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं.

कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज : राहिल ने बताया, विरोध करने पर आरोपी धमकी देने लगे. इसके बाद न्यायालय की शरण ली. इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सुमायरा और उनके बेटों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा

लखनऊः अचानक खुले नाले में जा गिरा तांगा और घोड़ा, दर्द से कराहता रहा बेजुबान

(जीएनएस)।

लखनऊ के पारा क्षेत्र में नगर निगम जोन-6 की बड़ी लापरवाही सामने आई है. बिना ढके खुले नाले में एक तांगा और घोड़ा गिर गए. स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से कड़ी मेहनत के बाद घोड़े और तांगे को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी है.

लखनऊ के पारा क्षेत्र में कल दोपहर नगर निगम जोन-6 की अनदेखी के कारण एक दर्दनाक हादसा होते-होते बचा. यहां सड़क किनारे बना एक नाला बिना ढक्कन के खुला पड़ा था, जिसमें एक घोड़ा अपने तांगे समेत जा गिरा.

यह घटना अधिकारियों की घोर लापरवाही को उजागर करती है. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. स्थानीय नागरिकों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और काफी संघर्ष के बाद

बेजुबान जानवर और तांगे को नाले से बाहर निकाला.

पारा क्षेत्र में खुले पड़े इस नाले ने राहगीरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है. कल दोपहर जब तांगा चालक वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक घोड़ा नियंत्रण खो बैठा और गहरे नाले में समा गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जोन-6 के जिम्मेदार अधिकारियों को बार-बार सूचित करने के बाद भी नाले को ढका नहीं गया. इस लापरवाही ने एक बेजुबान की जान जोखिम में डाल दी. मौके पर मौजूद भीड़ ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

नगर निगम ने 24 घंटे में लिया एक्शन

हादसे के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर उठे विरोध के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया. नगर निगम के ताजा बयान के मुताबिक, जिस गड्ढे या खुले नाले की वजह से यह हादसा हुआ था, उसे अब पूरी तरह भर दिया गया है. प्रशासन का दावा है कि 24 घंटे के भीतर जरूरी एक्शन लेते हुए रास्ता साफ कर दिया गया है. वहां यातायात के लिए कोई दिक्कत नहीं है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है.

अण्डर-16 बालक वर्गमें अरनव और बालिका में आशी चैम्पियन, डीपीएल लॉन टेनिस इंटर स्कूल चैम्पियनशिप

लखनऊ। दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) एल्डिको में गुरुवार को इंटर स्कूल लॉन टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। चैम्पियनशिप में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चें ने अण्डर-8, अण्डर-10, अण्डर-12 और अण्डर-16 बालक-बालिका वर्ग में प्रतिभाग किया। अण्डर-16 वर्ग में लामार्टीनियर कालेज के आर्यन चौहान और बालिका वर्ग में लामार्टीनियर की आशी शमशेर ने खिताब जीता। अण्डर-12 में डीपीएस एल्डिको के शुभी रंजन बालक वर्ग में और एपीएस नेहरु की विरिका अग्रवाल ने बालिका वर्ग में खिताब जीता।

2 से 5 फरवरी तक आयोजित चैम्पिश्नशिप में डीपीएस के शिक्षकों तथा प्राचार्य, खेल विभाग प्रमुख एवं विभागाध्यक्षों जैसे विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। इस आयोजन में

एकल एवं युगल मैचों की रोमांचक प्रतियोगिताएं हुईं, जिसमें अभय सिंह, आकाश गुप्ता, पुनीत कुमार, राहुल शर्मा, संजीव यादव तथा विजय सिंह जैसे शिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिले, जो स्कूल के मूल्यों के अनुरूप शारीरिक फिटनेस एवं खेलमान को बढ़ावा देते हैं। प्राचार्य मनीषा अंथवाल ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि यह टूनार्मेंट हमारी समग्र विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें स्पोर्ट्स एवं अन्य विभाग सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

प्रतियोगिता के परिणाम : अण्डर-8 बालक-बालिका मिक्सड : हिदांश यादव विजेता, सात्विक सिंह उपविजेता। अण्डर-8 बालिका : शैलवी जयसवाल विजेता, अण्डर-10 बालक : अदद्विक जैन विजेता, अभिराज राजपूत उपविजेता, अण्डर-10 बालिका : स्वर्णिम पाण्डेय, विजेता, कनिष्का पाठक, उपविजेता, अण्डर-12 बालक : शुभी रंजन, विजेता, वीरिका अग्रवाल उपविजेता, अण्डर-12 बालिका : अदविक जैन विजेता, रुद्रांश पाण्डेय, उपविजेता, अण्डर-16 बालक : आर्यन चौहान, विजेता, अभय पाल, उपविजेता, अण्डर-16 बालिका : आशी शमशेर विजेता, इक्षिता रंजन, उपविजेता।

लखनऊ के लिए खुशखबरीः 22 फरवरी को होगा ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण

नवाबों की नगरी लखनऊ वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गोमतीनगर से डालीगंज तक ग्रीन कॉरिडोर फेज-2 का काम पूरा हो गया है, जिसका लोकार्पण 22 फरवरी को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी है। शहर में एक प्रमुख इंफ्रा प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है और अब आगामी 22 फरवरी को इसे आम जनता को समर्पित किया जाएगा। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसका लोकार्पण करेंगे। जी हां बात गोमतीनगर के समतामूलक चौराहे से निशातगंज होते हुए हनुमान सेतु और आगे डालीगंज तक के ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे फेज की हो रही है।

इस कॉरिडोर के खुल जाने के बाद डालीगंज से गोमतीनगर तक का सफर सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। जबकि अभी इस पर लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। हर रोज एक लाख से ज्यादा लोग जाम में फंसकर इस सफर को पूरा करते हैं।

ग्रीन कॉरिडोर के फेज-2 उद्घाटन से इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी छऊअ इस ग्रीन कॉरिडोर को बना रहा है, जो दूसरे चरण में समतामूलक चौराहे से निशातगंज तक बना है। यह काम पूरा हो चुका है। निशातगंज चौराहे की री-डिजाइनिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और अब बस अंतिम चरण में फिनिशिंग का काम ही बचा है, जो तेजी से पूरा किया जा रहा है।

यही नहीं आगे भी बीरबल साहनी मार्ग से हनुमान सेतु तक सड़क चौड़ीकरण व डामरीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। यहां पर फ्लाइओवर का निर्माण भी पूरा हो गया है, जबकि चौराहे का काम भी अंतिम चरण में है। हनुमान सेतु से डालीगंज तक फ्लाइओवर बन चुका है। समतामूलक से निशातगंज तक का हिस्सा करीब एक महीने से तैयार है, लेकिन लोकार्पण के इंतजार में इसे बंद रखा गया है। अब 22 फरवरी को इस पूरे रूट को खोलने की तैयारी है।

बता दें कि क्कट से पक्का पुल तक ग्रीन कॉरिडोर के पहले चरण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इस हिस्से पर पिछले करीब डेढ़ वर्षों से ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी है। हालांकि, बता दें कि इस हिस्से का भी लोकार्पण नहीं हुआ था। आगामी 22 फरवरी के कार्यक्रम में इन दोनों ही चरणों का लोकार्पण एक साथ किया जाएगा।